साल में मोदी सरकार की शीर्ष उपलब्धियां और प्रगति

1. मजबूत हुई अर्थव्यवस्था

गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, नरेंद्र मोदी ने खुद को आर्थिक आंदोलन का महान समर्थक साबित किया था। नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था शीर्ष पर रही है।
उनके नेतृत्व में, गुजरात देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बन गया और उन्होंने बहुत सारी विदेशी कंपनियों और सरकारों के साथ समझौते किए। नरेंद्र मोदी उसी को बड़े स्तर पर दोहराने में सफल रहे हैं। उनकी विदेश यात्राओं ने जापान के साथ देश में पहली बुलेट ट्रेन में निवेश किया है। हालांकि दुनिया धीमी प्रगति दिखाती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की दर से प्रगति कर रही है, जिससे यह भविष्य के लिए सबसे सकारात्मक संकेतों में से एक है।

2. बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विदेश नीति मोदी की शीर्ष उपलब्धियों में से एक रही है।

कई विदेशी दौरों के लिए नरेंद्र मोदी की अक्सर विपक्ष द्वारा आलोचना की जाती रही है। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामाहोवा, हममें से कोई भी इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि उनकी यात्रा ने देश के लिए बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। चाहे वह बराक ओबामा के साथ गर्मजोशी से हो या जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ गंगा आरती में भाग लेने के लिए, नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े राजनयिकों के साथ दोस्ती की। यह उनके गतिशील नेतृत्व के कारण है कि यूएई ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बात की। भारत ने बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे देशों को वित्तीय मदद दी है और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा है। इसके अलावा, दक्षिण एशियाई उपग्रह लॉन्च करने से भारत की अगली एशियाई महाशक्ति बनने की योजना में एक लंबा रास्ता तय होगा।

3. महत्वपूर्ण मुद्दों पर दृष्टिकोण में बदलाव

पिछले प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में, भारत को शांति बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ एक रक्षात्मक देश माना जाता था। नरेंद्र मोदी ने संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए अधिक आक्रामक तरीका दिखाया है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट करने जैसी घटनाएं हमें इसकी एक झलक देती हैं। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश और दलाई लामा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चीन सरकार के साथ सरकार आमने-सामने आ गई है।

श्रीलंका में पिछले राष्ट्रपति चुनावों को भारतीय शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रभावित किए जाने की अफवाह थी। इसके अलावा, प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना, भारत ने इजरायल को खुला समर्थन दिया है और दोनों देश रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े कई सौदों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए डोकलाम गतिरोध के समय एक और ऐसी घटना हुई, जिसमें भारत ने अपना प्रतिरोध दिखाया और चीनी दबाव के खिलाफ हार नहीं मानी। इसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया और यह साबित कर दिया कि भारत ने अब अपना रुख अपनाना शुरू कर दिया है और दुनिया भर के देशों को भारत को अगली बार से ऐसे किसी भी मुद्दे में शामिल करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए।

4. बढ़ी हुई आंतरिक सुरक्षा

हालांकि सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है और पाकिस्तान द्वारा लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी है, जिसके परिणामस्वरूप सैनिकों की नियमित हताहत और माओवादियों की तरह आंतरिक खतरे भारत ने जिहादी आतंकवादियों से आंतरिक भागों को सुरक्षित करने में एक लंबा सफर तय किया है। पिछले कुछ वर्षों में, सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत सारी योजनाएं पटरी से उतर गई हैं। सांप्रदायिक हिंसा एक महत्वपूर्ण स्तर पर आ गई है और आखिरकार, देश मुख्यधारा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्पर है

। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया

नरेंद्र मोदी सरकार ने आम लोगों को सीधे प्रभावित करने के लिए कई पहल की हैं। मेक इन इंडिया को यह सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की गई थी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में अपनी योजनाएं शुरू करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार पैदा होता है और अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। मेक इन इंडिया ने शानदार गति प्राप्त की है और कई देशों ने संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ FDI और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए हैं।

साथ ही, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया और लाखों नागरिकों को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में लाया। साथ ही, ई-वे का प्रचार, जो 2020 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का वादा करता है, भविष्य में सफलता में एक महान उत्प्रेरक साबित होगा।

6स्वच्छ छवि वाली सरकार

भारत मेंको अक्सर राजनीति का पर्याय माना जाता है। हालांकि पिछली सरकार सीडब्ल्यूजी, कोलगेट और 2 जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों के लिए भारी आलोचनाओं के घेरे में आई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना नहीं किया है और राजनेताओं ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है और यह एक बड़ी मोदी उपलब्धि है।

प्रधान मंत्री ने अपने कार्यकाल में एक दिन की छुट्टी नहीं लेकर अपनी टीम का उदाहरण दिया है। साथ ही, बीकन के प्रतिबंध जैसी पहलों ने आम नागरिकों और सरकार के बीच संबंध बढ़ाए हैं। सुषमा स्वराज और सुरेश प्रभु जैसे मंत्रियों को अक्सर ट्विटर पर लोगों से सीधे संवाद करते और उनके सवालों का जवाब देते हुए देखा जाता है, नरेंद्र मोदी भी सामान्य मुद्दों पर बात करने के लिए नियमित रूप से मन की बात कार्यक्रम रखते हैं।

7. स्वच्छ भारत

जब इस पहल की घोषणा की गई थी, तो बहुत से लोगों को इस बात पर हंसी आई थी कि सरकार इतने छोटे मुद्दे को इतना महत्व दे रही है। हालाँकि, पिछले ढाई वर्षों में, इस क्षण ने गति पकड़ ली है और बड़े शहरों ने स्वच्छता के महत्व को महसूस करना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थान अब अतीत की तुलना में साफ-सुथरे हैं और आम जनता इसे एक व्यापक क्षण बनाने में लगी हुई है जहाँ हर कोई अपने कर्तव्यों के बारे में जानता है।

8. जीएसटी

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आजादी के बाद की सबसे बड़ी कर क्रांति के रूप में जाना जाता है, अंततः मंजूरी दे दी गई है और पहली जुलाई से लागू की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि नए सुधार से समझदार कर कोष्ठक द्वारा लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वस्तुओं और सेवाओं पर करों की दर पर एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश वस्तुएं जीएसटी के बाद सस्ती हो जाएंगी और इससे सरकार के इरादों में लोगों का भरोसा फिर से स्थापित हुआ है। जीएसटी से पहले, सरकार ने मध्यम वर्ग के बहुत से लोगों को प्रभावित करते हुए सबसे कम स्लैब में आयकर की दर 10% से घटाकर 5% कर दी थी।

9. ग्रामीण भारत परपर विशेष ध्यान

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनावर्तमान सरकार द्वारा सबसे अधिक सराहना की गई योजनाओं में से एक है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए अपनी सब्सिडी छोड़ने के लिए कहकर सामान्य लोगों को शामिल किया, उसे व्यापक रूप से सराहा गया है। इसके अलावा, कृषि सिचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं को ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सीधे ध्यान केंद्रित किया गया है।

हाल ही में, सरकार ने 100% भारतीय गांवों के विद्युतीकरण की भी घोषणा की है। हालांकि, आजादी के 70 साल हो चुके हैं, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह देखते हुए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले बिना बिजली के 18,000 से ज्यादा गांव थे।

10.नीती आयोग

भारत को आजादी मिलने के बाद सेने योजना आयोग द्वारा केंद्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं और निष्पादन किए। मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीती आयोग को पेश किया, जो नियोजन के मामलों पर राज्यों को समान शक्ति देने का वादा करता है। इसके अलावा, सरकार ने 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है और अब 3 साल की योजनाएं और 15 साल की योजनाएं स्पष्ट एजेंडा और उद्देश्यों के साथ होंगी। नीती आयोग सभी वर्गों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों और एमएसएमई का समर्थन करने का आह्वान करता है। Niti Aayog एक CEO और जवाबदेह प्रतिनिधियों के साथ एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में काम करती है।

11. महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त रुख

सत्ता में नवीनतम सरकार के साथ, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होती दिख रही है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तालक को असंवैधानिक घोषित किया और सरकार से 6 महीने के भीतर एक कानून लाने को कहा। फैसले ने मिश्रित समीक्षाओं को आकर्षित किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं सरकार के खुले समर्थन में आ रही हैं और साथ ही विपक्ष एक बार फिर सरकार का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, एक बात साबित हो गई है कि इन फैसलों में हिम्मत की जरूरत है और मौजूदा सरकार के पास पर्याप्त है।

ये पिछले 4 वर्षों में मोदी सरकार की कुछ उपलब्धियाँ थीं। हालाँकि अगले कुछ वर्षों में और भी कई मुद्दे सामने आने हैं, फिर भी सरकार ने अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एहसास कराकर नागरिकों में आशा की भावना पैदा की है। आशा करते हैं कि सरकार शेष अवधि में भी हासिल करती रहेगी।

12. समाज कल्याण योजनाएं बड़े पैमाने पर

मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजनाओं को शुरू करने और उन्हें समयबद्धता के तहत बड़े पैमाने पर वितरित करने के लिए अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के क्रियान्वयन की गति सरकार की प्रतिबद्धता है कि सरकार क्या हासिल कर सकती है।

पीएमजेडीवाई दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और हाशिए वाले वर्गों को बैंकिंग प्रणाली में लाना है, और उन्हें सरकार से सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

पीएमजेडीवाई सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक रिसाव और सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इस प्रकार लाभ सुनिश्चित करना लाभार्थी तक पहुंचता है। मई 2018 तक, 31.60 करोड़ लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया गया है। बचत खाता खोलने के परिणामस्वरूप कुल जमा राशि 81,203.59 करोड़ रुपये है। 23.80 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और अब एटीएम तक पहुंच सकते हैं।

13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS)

मोदी सरकार की एक बड़ी पहल है? एनएचपीएस का लक्ष्य गंभीर बीमारियों के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस योजना का उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों या समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 50 करोड़ लोगों को कवर करना है।

सबसे गरीब लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के अलावा, इस योजना का देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।

14. बीजेपी को एक पैन-इंडिया पार्टी में बदलना

स्वतंत्रता के समय से, जनसंघ, बीजेपी के पहले अवतार, ने खुद को एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष किया था, जो पैन-इंडिया आधार पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने में सक्षम थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी एक स्थायी चुनौती देने के करीब पहुंच गई, लेकिन जल्द ही कांग्रेस पार्टी प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने में सक्षम हो गई।

एक अखिल भारतीय राजनीतिक बल के रूप में बीजेपी का पुनरुत्थान 2014 के आम चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। उनकी पार्टी नेतृत्व की कमान और यूपीए के खिलाफ चुनावी रणनीति का निर्देशन भारतीय राजनीति में निर्णायक क्षण बन गया।

उनकी नाटकीय जीत, मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट संचार और एक गैर-बकवास दृष्टिकोण ने एक समर्थक नौकरशाही में एक कुशल नौकरशाही को सक्रिय करने में मदद की है। उनके नेतृत्व में पूरी सरकार आज भ्रष्टाचार मुक्त प्रतिष्ठा हासिल करती है। यह उस देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जहां वर्षों में भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया था।

UPA II के तहत, भारत बहुत ही रणनीतिक दिशा या मजबूत घरेलू लक्ष्यों के बिना एक राष्ट्र था जो परिवर्तनशील और अभी तक एकजुट थे। पीएम मोदी और उनकी पार्टी ने उस धारणा को सफलतापूर्वक बदल दिया है। विविध रूप से, और अक्सर, परस्पर विरोधी हितों वाले राजनीतिक रूप से खंडित देश में, मोदी सरकार एक गतिशील भारत की अवधारणा में लोगों के बीच विश्वास और गर्व की भावना पैदा करने में सक्षम रही है। यह एक बड़ी उपलब्धि है।